राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 145

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, रविवार, 3 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

'रांगा माटी' ने बदली बंगाल के गांवों की परिपाटी

कोलकाता : बंगाल के माओवाद प्रभावित मेदिनीपुर, बांकुड़ा व वीरभूम जिलों में एक

व्यक्ति ने विकास का पौधा रोपा जो अब फल देने लगा है। कभी दो जून की रोटी को तरसने वाले कई गांवों के सैकड़ों परिवार आज खुशहाल हैं। नई इबारत लिखने वाले ये शख्स हैं संजय गुहा ठाकुरता। (पेज-11)

रविवार विशेष

दिल जीतेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 'नया सीजन'

पीलीभीत : उप्र के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 'नया सीजन' लोगों का दिल जीत लेगा।

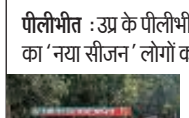

जंगल के दर्शनीय स्थलों और निकट के गांवों में पेइंग गेस्ट रूम तैयार किए गए हैं, जहां सैलानियों को स्थानीय व्यंजनों का जायका भी मिलेगा। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

हरियाणा में हुड्डा होंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता

नई दिल्ली : हरियाणा में चुनाव से पूर्व की सियासी चूक से सबक लेते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने में जरा भी देरी नहीं की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधायक दल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अगले ही दिन हुड्डा को नेता नियुक्त कर दिया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

चंद्रयान-2 कहानी का अंत नहीं है : सिवन

नई दिल्ली : इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा कि हम चंद्रमा पर सही तरीके से उतरने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन यह चंद्रयान-2 कहानी का अंत नहीं है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इसरो अपने सभी अनुभवों, ज्ञान और तकनीकी कौशल की मदद से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

लश्कर और जैश को रोकने में विफल रहा पाकिस्तान

वाशिंगटन : पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकी संगठन लश्कर और जैश ए मुहम्मद को मिलने वाले धन, आतंकियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण को रोक पाने में विफल रहा है। आतंकियों ने चुनाव लड़कर सत्ता में पहुंचने की भी कोशिश की। यह बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में कही गई है।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

भुवनेश्वर : भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को यहां ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे मुकाबले में अमेरिका से हारने के बाद भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारतीय महिला टीम को अमेरिका ने 4-1 से मात दी।

अपने हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे : मोदी

कूटनीति ▶ आसियान सम्मेलन में भाग लेने थाइलैंड पहुंचे पीएम, कल क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की बैठक को करेंगे संबोधित

कहा, पारस्परिक रूप से लाभप्रद आरसेप सभी सदस्य देशों के हित में

बैंकॉक, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में अपने हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत यह देखेगा कि आरसेप समझौते में व्यापार, सेवाओं और निवेश पर उसकी चिंताओं को पूरी तरह से समायोजित किया जा रहा है या नहीं। मोदी तीन अहम सम्मेलनों में शामिल होने तीन दिनी यात्रा पर शनिवार को थाइलैंड पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी तीन नवंबर को 16वें भारत-आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि, चार नवंबर को आरसेप संधि पर सदस्य देशों की तीसरी शिखर बैठक को संबोधित करेंगे। वह चार नवंबर को ही 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। आरसेप की लंबे समय से जारी वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने 'उचित प्रस्तावों' को स्पष्ट तरीके से आगे रखा है। भारत मुक्त व्यापार के लिए 'ईमानदारी' से वार्ता कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट मानना है कि पारस्परिक रूप से लाभप्रद आरसेप, जिससे सभी पक्ष यथोचित लाभ प्राप्त करते हैं, वह भारत समेत वार्ता में शामिल अन्य सभी देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत शिखर बैठक में आरसेप की वार्ता में प्रगति की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी 10 आसियान देशों (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ) और छह व्यापार देशों -भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वार्ताकारों की बातचीत के दौरान की। आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाइलैंड, फिलीपींस, लाओस और विएतनाम शामिल हैं। वहीं, विभिन्न राजनयिक सूत्रों ने इस बात पुष्टि की कि भारत को छोड़कर सभी 15 सदस्य देशों के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और वह सोमवार की बैठक में इसे अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे।

बैंकॉक में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते भारतीय समुदाय के लोग। प्रेट्र

इससे पहले, थाइलैंड रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान वह बैंकॉक में मौजूद कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा, 'आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन हमारे कूटनीतिक कैलेंडर का एक अभिन्न अंग और हमारी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्वपूर्ण घटक है। आसियान के साथ हमारी साझेदारी संपर्क, क्षमता निर्माण, वाणिज्य और संस्कृति के प्रमुख स्तंभों पर बनी है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आसियान भागीदारों के साथ सहयोगात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और आसियान तथा उसके नेतृत्व को मजबूत करने वाले तंत्र की योजनाओं पर, संपर्क बढ़ाने पर (समुद्र, भूमि, वायु, डिजिटल और लोगों के बीच), आर्थिक भागीदारी को गहरा करने तथा समुद्री सहयोग के विस्तार पर भी गौर करेंगे।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के मायने, काम और प्रभाव

क्या है आरसेप?

साल 2012 में शुरू हुआ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसेप चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत का 10 सदस्यीय आसियान गुट के साथ एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है। इस साझेदारी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बाहर है।

दुनिया का सबसे बड़ा होगा यह व्यापार समझौता

आरसेप पर अगर सदस्य देशों के बीच सहमति बन जाती है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। इसके सदस्य 16 देशों में 3 .5 अरब (दुनिया की आबादी 7 .7 अरब है) लोग रहते हैं और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा यहां है।

भारत में क्यों हो रहा विरोध?

आरसेप में भारत के शामिल होने का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही यह बताया जा रहा है कि आरसेप से आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता के और सभी के लिए फायदेमंद व्यापार अनुबंधों को बढ़ावा मिलेगा, पर सच यह है कि इससे असमानता, एकतरफा व्यापार व्यवस्था व पूंजीवादी नियंत्रण के कारण कारपोरेट नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार खत्म होने और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने चुनौतियां और गहरी होंगी।

चीन का बढ़ेगा दबदबा

आरसेप से अमेरिका के बाहर रहने से सीधा फायदा चीन को होगा। चीन इसका नेतृत्व भी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि आरसेप से चीन का उसके पड़ोसी देशों में प्रभुत्व और बढ़ेगा, क्योंकि यहां उसे अमेरिका से बड़ी चुनौती नहीं मिलती है।

सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले में चार को सजा-ए-मौत

जासं, रामपुर

उप्र के रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मुकदमे में शनिवार को तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। हमले में दोषी दो पाकिस्तानी आतंकियों सहित चार को फांसी की सजा सुनाई। इसी मुकदमे में अदालत ने मुरादाबाद के जंग बहादुर बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि फर्जी पासपोर्ट और पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए मुंबई के फहीम अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

हमले में सात जवान हुए थे शहीद, एक रिक्शा चालक की भी हुई थी मौत

31 दिसंबर 2007 की रात पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा था। रात ढाई बजे आतंकियों ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला किया था। आतंकी दिल्ली-लखनऊ मार्ग स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर एक से अंदर घुसे थे। यहां गेट से पहले रेलवे क्रॉसिंग भी है। क्रॉसिंग पर बने गेटमैन के केबिन के पास तीन जवान आग जलाकर बैठे थे। आतंकियों ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ गेट पर मौजूद जवानों पर एके-47 से गोलियां बरसाईं और हैंड ग्रेनेड फेंके। यहां से आतंकी सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के अंदर घुस गए थे और वहां भी कत्लेआम किया था। बाद में आतंकी सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की दीवार कूदकर भाग गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे। जबकि एक एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने हमले के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। मुकदमे में 38 की गवाही हुई। 19 अक्टूबर को मुकदमे में बहस पूरी हो गई। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। (पेज-5 भी देखें)

शरीफ

सबाउद्दीन

इमरान

मुहम्मद फारुख

फहीम अरशद अंसारी

बाबा उर्फ जंगबहादुर

इन्हें मिली फांसी की सजा

1 **शरीफ उर्फ सुहेल** : ग्राम बदनपुर, थाना खजुरिया, जिला रामपुर, उप्र

2 **सहाबुद्दीन उर्फ सवाह** : गंधवार बायां पंडौल, थाना सकरी, जिला मधबुनी, बिहार

3 **इमरान शहजाद उर्फ अजय** : समानी, थाना चौक सदर, जिला विम्बर, गुलाम कश्मीर

4 **मोहम्मद फारुख उर्फ अबू** : सांगढ़ीवाला, धौकल थाना सदर, जिला गुन्जरावाला, पंजाब, पाकिस्तान।

इन्हें मिली उम्र कैद

5 **बाबा उर्फ जंगबहादुर** : मिलक, कांगड़ू, थाना मूंढापांडे, जिला मुरादाबाद, उप्र

6 **फहीम अरशद अंसारी** : चाल नं. 330, एमजी रोड, मुंबई

दोषमुक्त किए गए आरोपित

1 **मुहम्मद कौसर** : आजाद नगर थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़, उप्र

2 **गुलाब खान** : शाहगढ़, थाना बहेड़ी, जिला बरेली उप्र

पाक-चीन को संदेश, गुलाम कश्मीर हमारा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- भारत ने जारी किया जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र
- मुजफ्फराबाद व मीरपुर जिलों को मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में 22 जिले

जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नया नक्शा जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत का भी नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। अब भारत में 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ी तल्खी के बाद यह नया मानचित्र दोनों देशों को भारत का जवाब माना जा रहा है। हाल ही में जम्मू के राजौरी में सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर की कसक मेरे अंदर है।

अक्साई चिन से लेकर गिलगित-बाल्टिस्तान तक लद्दाख में शामिल : सर्वे जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नक्शे में पूरा गुलाम कश्मीर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। गुलाम कश्मीर के गिलगित, गिलगित बजारत, चिलहास व ट्राइबल टेरीटरी जिलों को लद्दाख के दो जिलों कारगिल व लेह में शामिल किया गया है। अक्साई चिन भी लद्दाख में ही है, जबकि गुलाम कश्मीर के दो जिलों मुजफ्फराबाद और मीरपुर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया है। गुलाम कश्मीर के इस पूरे हिस्से को आम बोलचाल में गिलगित-बाल्टीस्तान कहा जाता है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नया राजनीतिक मानचित्र।

केंद्र शासित लद्दाख में दो जिले

लेह (गिलगित, बजारत, चिलहास और ट्राइबल टेरीटरी भी शामिल)

कारगिल (लेह और लद्दाख का अन्य सारा हिस्सा)

1947 तक सिर्फ 14 जिले

वर्ष 1947 तक जम्मू-कश्मीर में 14 जिले थे। 2019 तक आते-आते तत्कालीन राज्य सरकारों ने इन 14 जिलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 जिले बना दिए थे। इन 28 जिलों में से मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, गिलगित बजारत, चिलहास और ट्राइबल टेरिटरी गुलाम कश्मीर में पड़ते थे। अब इन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा बनाया गया है।

गुलाम कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा : केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से लद्दाख (दो जिले) अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर के 20 जिले रह गए थे। अब मुजफ्फराबाद और मीरपुर जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फिर 22 जिले हो गए हैं। हालांकि भारत पहले भी गुलाम कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाता था और राज्य विधानसभा में गुलाम कश्मीर की 24 सीटों को खाली भी रखा जाता है। अब गुलाम कश्मीर के को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिलों के रूप में शामिल किया गया है।

अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 22 जिले : कठुआ, जम्मू, सांबा, ऊधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, रामबन, पुंछ, कुलगाम, शोपियां, श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, पुलवामा, गांदरबल, बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, मीरपुर और मुजफ्फराबाद।

दिल्ली में वकीलों-पुलिस के बीच हिंसक झड़प

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- तीस हजारी कोर्ट में हुई घटना, गोली लगने से एक वकील घायल
- वकीलों ने पुलिस की जिप्सी व 13 बाइकें फूंकीं, कैदी वैन में तोड़-फोड़

तीस हजारी कोर्ट परिसर में लॉकअप के बाहर कार खड़ी करने को लेकर शनिवार को वकीलों व पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस की गोली लगने से एक वकील घायल हो गया। दो अन्य वकील भी चोटिल हो गए। इसके बाद वकीलों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस की जीप और 13 मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। कैदियों को लेकर आए सात वाहनों में भी तोड़फोड़ की।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट लॉकअप के सामने कैदी को लेकर आने वाली वैन समेत पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे एक वकील वहां अपनी कार खड़ी करने लगे। पेशी के लिए कैदियों को लेकर आए तीसरी बटालियन के जवानों ने उन्हें गाड़ी दूसरी जगह खड़ी करने को कहा। आरोप है कि कहासुनी के बीच पुलिसकर्मियों ने वकील और उनके दो साथियों को लॉकअप में बंद कर पीटना शुरू कर दिया। सूचना पाकर अन्य वकील वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, वकीलों की भीड़ लॉकअप तोड़कर अंदर बंद सौ से ज्यादा कैदियों को भगाने का प्रयास करने लगी। एक पुलिसकर्मी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पिस्टल से हवा में गोली चला दी, जो वहां मौजूद वकील रंजीत सिंह मलिक के सीने में लग गई। साथियों के घायल होने पर वकीलों ने आपा खो दिया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही आगजनी करने लगे। पुलिस की जीप, कैदियों को लेकर आए वाहनों और आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। पुलिस अफसरों को बंधक बना लिया और उनसे बदसलूकी की। परिसर में मौजूद आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। कोर्ट परिसर पर वकीलों का कब्जा था तो बाहर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले थे। कई जिलों व थानों से पुलिस बुला ली गई। शाम करीब पांच बजे लाठीचार्ज करते हुए पुलिसकर्मी कोर्ट में दाखिल हुए और वकीलों को हटाया।

तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के दौरान फूंकी गई गाड़ी। प्रेट्र

आरोपित पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग : वकीलों ने पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांग पूरी न होने पर सोमवार को दिल्ली की सभी अदालतों में काम ठप कर देंगे।

कश्मीर के 450 लोगों की विदेश यात्रा पर रोक

श्रीनगर : केंद्र शासित (यूटी) प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने कश्मीर के हालात पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार को रोकने के लिए लगभग 450 लोगों की सूची तैयार कर उनकी विदेश यात्राओं पर कथित तौर पर रोक लगा रखी है। हालांकि, अधिकारिक तौर पर सूची का एलान नहीं किया है। संबंधित प्रशासन की मानें तो यह एक टेंपोरेरी नो फ्लाई लिस्ट है। सूत्रों ने बताया कि है खुफिया तंत्र ने ऐसे कई लोगों की सूची तैयार की है। (पेज-6)

वाहनों में लगाने के लिए पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा फास्टैग

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल की अदायगी के लिए जरूरी फास्टैग शीघ्र ही पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा। इससे पेट्रोल व पार्किंग शुल्क का भी भुगतान किया जा सकेगा। यही नहीं, स्टेट हाईवे तथा शहरी टोल प्लाजा पर भी फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स स्वीकार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियां जोर-शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तहत पहली दिसंबर से सभी वाहनों में फास्टैग लगाना होगा। (पेज-12)

ऐतिहासिक सत्र

पंजाब विधानसभा में होगा विशेष सत्र का आयोजन, पहली बार सदन में होगी गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर चर्चा, दो सीएम, दो राज्यपाल, पूर्व पीएम मनमोहन सदन में रहेंगे मौजूद

नानक की सीख सुनेंगे पंजाब-हरियाणा के विधायक

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

550 वें प्रकाशोत्सव को समर्पित विशेष सत्र कई मायनों में होगा खास

6 नवंबर को उपराष्ट्रपति करेंगे विशेष सत्र की अध्यक्षता

53 साल बाद पंजाब व हरियाणा के विधायक एक साथ बैठेंगे

पंजाब विधानसभा एक ऐतिहासिक सत्र की साक्षी बनने के लिए तैयार है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित करते हुए छह नवंबर को यहां विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में सिर्फ गुरु नानक जी की शिक्षाओं और उनके जीवन दर्शन पर चर्चा होगी। यह सत्र इस मायने में भी विशेष होगा कि इस दौरान 53 साल बाद पंजाब और हरियाणा के विधायक एक साथ बैठेंगे। सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे।

पंजाब और हरियाणा के बीच विभिन्न विवादित मसलों को देखते हुए इस सत्र को काफी खास माना जा रहा है। दोनों राज्य अपने आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने के बजाय अदालत का सहारा लेते हैं। वहीं गुरु नानक साहिब ने मतभेदों को हमेशा आपसी सहमति से सुलझाने का रास्ता दिखाया है। अपने इस जीवन दर्शन को प्रसारित करने के लिए उन्होंने विभिन्न धार्मिक यात्राएं भी की थीं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह विशेष सत्र दोनों राज्यों के आपसी संबंधों की दिशा में नई इबारत लिख सकता है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने बताया कि गुरु नानक साहिब का पूरा जीवन आपसी भाईचारे और सब के भले को समर्पित रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 550वें प्रकाशोत्सव पर हमें उनके जीवन दर्शन पर बात करने का मौका मिल रहा है। यह ऐतिहासिक दिन होगा जब दो राज्यों के विधायक, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री विधानसभा में उपस्थित होंगे और गुरु नानक साहिब की शिक्षाओं पर बात होगी।

पंजाब विधानसभा के स्पीकर, विपक्ष के नेता दस-दस मिनट बोलेंगे। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री 15-15 मिनट बोलेंगे। उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के लिए समय तय नहीं किया गया है। विशेष सत्र के बाद सदन को स्थगित करके फिर से शुरू किया जाएगा और तब दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

सदन में की जाएगी विशेष व्यवस्था : पहली बार विधानसभा में स्पीकर के आसन को हटाकर एक डायस बनाया जाएगा और सात प्रमुख शख्सियतें बैठेंगी। इनमें उपराष्ट्रपति नायडू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह शामिल हैं।

सदैव प्रासंगिक है गुरु नानक जी की सीख : गुरु नानक साहिब ने अपने जीवन में चार विशेष धार्मिक यात्राएं की थीं। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारा और सरबत के भले को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। उनकी शिक्षाएं वर्तमान समय में कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं, जब लोग छोटी-छोटी बातों पर लड़ने को तैयार बैठे हैं। गुरु नानक जी का जीवन सत्ता से भयभीत हुए बिना अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भी अनुकरणीय रहा। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी आवाज बुलंद की थी।

दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के लिए पंजाब भी दोषी : अमरिंदर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब के सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर कहा-राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समस्या का हल हो
- उठाया सवाल, वह देश विकसित कैसे हो सकता है जिसकी राजधानी गैस चैंबर बन गई हो

दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगने के दूसरे दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावनात्मक पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति पर गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है। अमरिंदर ने पीएम से सियासी और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर इस समस्या पर एक राय बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही कहा कि पंजाब अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेवारी समझे। चिट्ठी में उन्होंने अपनी मांग दोहराई है कि पराली की समस्या के निपटारे के लिए किसानों को सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने लिखा है, 'कोई भी भारतीय, खास तौर पर पंजाबी राष्ट्रीय राजधानी में हमारे भाइयों के साथ घट रही त्रासदी से बेखबर नहीं है। मेरे अपने बच्चे, पोते-पोतियां दिल्ली में रहते हैं जो शहर की जहरीली हवा के कारण लोगों की दुर्दशा को समझते हैं। उस मुल्क को विकसित कैसे कहा जा सकता है जिसकी राजधानी को गैस चैंबर में बदल दिया गया हो। वह भी तब जब ऐसे हालात कुदरती आपदा के कारण नहीं बल्कि मानवीय गलती से पैदा हुए हों।' अमरिंदर के मुताबिक, दिल्ली और केंद्र सरकार समेत समूचे मुल्क ने विभिन्न गलतियों से ऐसे भयानक हालात पैदा होने की इजाजत दे दी है। पराली का धुआं गलत दिशा में बहने वाली हवाओं से दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा हुई।

अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

किसानों पर और सख्ती नहीं कर सकते : कैप्टन ने कहा, पंजाब ने पराली जलाने के विरुद्ध कानून को जहां तक संभव हुआ, लागू करने की कोशिश की। किसानों पर जुर्माने भी किए। हालांकि किसानों को सजा देना उनके जमीर के विरुद्ध है, लेकिन सख्ती हो रही है। किसानों को हाशिये पर नहीं ले जा सकते। उन्होंने पीएम से पूछा है कि आप बताएं कि इस समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

मनोहर ने लिखा जावडेकर को पत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को प्रदूषण के बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति, संस्था या सरकार जिम्मेदार नहीं है। सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए। (पेज-2 भी देखें)